

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश

1250, तुलसीनगर पिन कोड - 462003

दूरभाष - 0755- 2556916

ई-मेल : dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/दि.स/एफ.न.18/2022/ 155
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/01/2022

समस्त

संयुक्त / उप संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र.

विषय:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 अनुसार दिव्यांगजनों को प्रदाय किये जाने वाला कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र के फॉर्मेट के संबंध में।

जैसा की आप को विदित है कि नेशनल ट्रस्ट ऐक्ट 1999 अंतर्गत दिव्यांगता की 4 श्रेणियों यथा स्वपराणयता, प्रमस्तिष्यघाट, मानसिक मंदता एवं बहुविकलांगता ग्रस्त दिव्यांगजनों हेतु जिला स्तर पर लोकल लेवल कमेटी द्वारा कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र प्रदाय किया जा रहे है, उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के **सेक्शन 14** अनुसार ऐसे दिव्यांगजन जो कानूनी बाध्यकारी निर्णय लेने में अक्षम है उनके लिये पूर्ण या सीमित रूप से किसी व्यक्ति/ संस्था को कानूनी संरक्षणता प्रदाय करने का प्रावधान किया गया है साथ ही उक्त अधिनियम अनुसार दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुक्रम में प्रदेश स्तर पर तैयार किये गये नियम 2017 के **सेक्शन 6** अनुसार जिला कलेक्टर को दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र देने हेतु अधिकार प्रदाय किये गये है। उल्लेखनीय है कि जिला स्तर पर दिव्यांगजनों को प्रदाय किये जाने वाला कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र का कोई **स्टेन्डर्ड फॉर्मेट** निर्धारित नहीं है।

अतः ऐसे दिव्यांगजन जो कानूनी बाध्यकारी निर्णय लेने में अक्षम है उनके लिये पूर्ण या सीमित रूप से किसी व्यक्ति/ संस्था को कानूनी संरक्षणता प्रदाय करने हेतु जिला स्तर पर बनाये जाने वाले कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र का राज्य स्तर से **स्टेन्डर्ड फॉर्मेट** तैयार किया गया है, जिसका प्रारूप परिशिष्ट - "अ" पर संलग्न है। उक्त फॉर्मेट में ही जिला स्तर पर नियमानुसार कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र बनाया जाना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक (दि.स)

वास्ते आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र.

क्रमांक/दि.स/2022/ 156

भोपाल दिनांक 27/01/22

प्रतिलिपी :-

1. उप सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ ।
2. समस्त कलेक्टर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संयुक्त संचालक (दि.स)
वास्ते आयुक्त
27/01/2022

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र.

example

5/2/4

Office of the District Magistrate

Social Justice & Disabled Welfare Department, Govt. of Madhya Pradesh
Kothi Palace, Ujjain (M.P.) 456010 Phone No. 07342516135 Email - dmujjain@nic.in

Certificate No. -

Date: __/__/__



Certificate of Appointment of Guardian under RPwD Act. 2016

[See Section 14 of Rights of Persons with Disabilities Act 2016]

[See Rule 6 of Madhya Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules 2017, on back side of this certificate]

Mr./Ms. _____ (Name of PwD's) aged _____ Yrs
having Aadhar Card No. _____ & UDID Card No. / Disability
Certificate No. _____ Dated _____ who is
unable to take legally binding decisions and required further support of a Limited / Total
Guardianship to take legally binding decisions on his / her behalf.

The competent authority considered the application made by Mr./Ms.
_____ for appointment of Guardianship and hereby confirms its
decision as under:

1. Name of the Guardian _____
2. Father's Name _____
3. Aadhar Card No. of the Guardian _____
4. Address of the Guardian _____
5. Type of Guardianship (Limited or Total Support) _____

Please Paste
Joint Passport Photo

In case of Limited Guardianship please tick the appropriate option /options.

- Maintenance and Residential Care ☐
- Management of Movable Property ☐
- Management of immovable Property ☐

Place, Ujjain

Authorized Signature
Registration Authority Seal

555

Rule 6 of Madhya Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules 2017

6 - Legal Assistance and limited guardianship to persons with disability. –

1. Persons with disability who are not living with family and requiring support for exercising legal rights, the Collector shall provide legal assistance through District Legal Aid Officer.
2. The Collector shall be the competent authority for granting limited guardianship to such persons with disability who are in need of taking decision in the cases of legal binding.
3. The competent authority shall ensure that guardianship is needed to the person with disability who are unable to take decision on legal basis.
4. The Collector shall, sou-motu or after receiving application, take action immediately :

Provided that the consent of the person, who agree to act as a limited guardian, shall also be obtained before grant of such limited guardianship. The period for limited guardianship shall be determined by the Collector according to the need.

5. **In case of disabled woman, the limited guardian shall be a woman.**
6. The limited guardian appointed under sub-rule (1) shall consult the person with disabilities in all matters before taking any decision of legal action in this behalf.
7. The limited guardian shall ensure that the decision of legal action taken on behalf of the person with disability is in the interest of the disabled person.

~~*~~